

करनाल चीनी मिल में पांच लाख किराये पर कंप्रेसर, जबकि मार्केट में नया कंप्रेसर 4,10,000 का !

हरियाणा की चीनी मिलों में रिश्वत का बाजार गर्म, छोटे कलपुजों की खरीदारी में लाखों के वारे-न्यारे

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

करनाल: जब पूरे देश में सरकारी संपत्तियों और संसाधनों की लूट मची हुई है तो भला उसमें करनाल कैसे पीछे रहेगा। करनाल सहकारी शुगर मिल में भी सरकारी धन को लूटा और बर्बाद किया जा रहा है। इस चीनी मिल में किराये पर मंगाये गए एक कंप्रेसर की आड़ में मचाई गई लूट की कहानी सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा सरकार कांग्रेस के जिस भ्रष्टाचार की दुहाई देकर सत्ता में आई थी, उसने भी सरकारी संसाधनों और पैसे की लूट का वही रास्ता अपनाया जैसा आरोप वह कांग्रेस पर लगाती रही है।

चीनी मिलों में पेरार्ई का सीजन अधिकतम पांच महीने का होता है। करनाल सहकारी चीनी मिल के प्रबंधन ने सीजन के लिए यानी पांच महीने के लिए 200 सीएफएम क्षमता का एक एयर कंप्रेसर पांच लाख किराये पर लिया। यानी हर महीने का एक लाख रुपये किराया। यह कंप्रेसर नई दिल्ली के कालूसराय स्थित जीजीएस कंप्रेसर्स से मंगाया गया। मजदूर मोर्चा संवाददाता ने इस बारे में जब छानबीन की तो चीनी मिल के सूत्रों ने ही इस खरीदफरोख्त की आड़ में की गई



धांधली की सूचना दी।

इसके बाद मजदूर मोर्चा संवाददाता ने अहमदाबाद, गुजरात की जानी-मानी मंत्रा टेक्नॉलजी से इस बारे में लिखित सूचना मांगी कि नया एयर कंप्रेसर कितने का मिलेगा। मंत्रा टेक्नॉलजी ने मजदूर मोर्चा

संवाददाता को जवाब दिया कि 217 सीएफएम क्षमता का एयर कंप्रेसर 4,10,000 रुपये में वे सप्लाई कर सकते हैं। यानी शुगर मिल इसे स्थायी रूप से लगा सकता है। मंत्रा टेक्नॉलजी ने यह भी बताया कि इस एयर कंप्रेसर की वारंटी

एक साल की होगी। किसी भी खराबी पर इसके पुर्जे बदल दिए जाएंगे।

इस छानबीन से साफ हो गया कि करनाल सहकारी चीनी मिल प्रबंधन ने किराये पर एयर कंप्रेसर लेने के लिए पांच लाख रुपये खर्च कर दिए, जबकि मार्केट में उससे कम पैसे में स्थायी एयर कंप्रेसर चीनी मिल प्रबंधन खरीद सकता था। लेकिन विभिन्न विभागों द्वारा इस मामले में रिश्वत और कमीशनखोरी की सेटिंग इस तरह की गई है कि उसमें लाखों रुपये के वारे-न्यारे हो जाते हैं। मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली मार्केट में पांच महीने के लिए मिलने वाले एयर कंप्रेसर का किराया दो से ढाई लाख के बीच में पड़ता है। शेष ढाई लाख का बटवारा अफसरों ने आपस में कर लिया है।

हरियाणा की एक चीनी मिल से बतौर जीएम रिटायर हुए एक पूर्व अधिकारी ने मजदूर मोर्चा को बताया कि सीजन में जब सरकारी और सहकारी चीनी मिलें चालू होती हैं तो एयर कंप्रेसर से लेकर छोटे-छोटे नट-बोल्ट की खरीदारी में लाखों का घपला किया जाता है। सहकारी चीनी मिलों में चूँकि राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण होता है तो वहां सबकुछ बहुत

संगठित तरीके से अंजाम दिया जाता है। चीनी मिल के तकनीकी कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार होता हुआ देखते रहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि नियंत्रण किसी आईएएस या पीसीएस अफसर के पास होता है।

महाघपले की आहट

करनाल सहकारी चीनी मिल में हुए इस घपले की आड़ में दरअसल महाघपला किया गया है। चीनी मिल ने किराये पर एयर कंप्रेसर जिस फर्म जीजीएस कंप्रेसर्स से लिया है, उसका पता विजय मंडल एनक्लेव कालूसराय, नई दिल्ली दिया गया है लेकिन उस इलाके में फिटजी जैसे ज्यादातर शिक्षण संस्थान चलते हैं। वहां इस तरह की फर्म सार्वजनिक रूप से बोर्ड वगैरह लगाकर काम नहीं करती है। कालूसराय में आपको आईआईटी की तैयारी कराने वाली दुकानें और दफतर तो मिल जायेंगे लेकिन जीजीएस कंप्रेसर्स का मिलना नामुमकिन जैसा है। यह इलाका पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है लेकिन लोगों ने अपने घर के एक हिस्से को तमाम शिक्षण संस्थाओं को किराये पर दे रखा है। किसी निष्पक्ष एजेंसी की जांच में जीजीएस कंप्रेसर्स के बारे में और भी जानकारी आ सकती है।

करनाल नगर निगम को पता ही नहीं कितनी बिल्डिंगें बन रहीं!



मजदूर मोर्चा ब्यूरो

करनाल: नगर निगम करनाल के पास यह जानकारी नहीं है कि शहर में कितने घरेलू और कितने व्यावसायिक भवन निर्माणाधीन हैं। यानी इसका मतलब है कि करनाल में जितने भी निर्माण वैध या अवैध हो रहे हैं, उसकी जानकारी निगम के पास नहीं है। यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई से पता चला है कि करनाल नगर निगम के अधिकारी किस तरह अकॉउंट भ्रष्टाचार में डूबकर शहर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहा है। सीएम सिटी कहलाने के बावजूद करनाल नगर निगम के बेईमान अफसरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

करनाल के रहने वाले नरेंद्र सूखन एडवोकेट ने एक आरटीआई के जरिए करनाल नगर निगम से पूछा था कि शहर में कितने घरेलू और व्यावसायिक भवन निर्माणाधीन हैं। इनमें से जो अवैध हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नरेंद्र सूखन एडवोकेट ने यह भी पूछा था कि कितने भवन मालिकों ने अपनी बिल्डिंगों का साइट प्लान (नक्शा) करनाल नगर निगम से मंजूर कराया और कितनों ने साइट प्लान मंजूर नहीं कराया।

नरेंद्र सूखन की इस आरटीआई पर नगर निगम को सांप्रसूध गया। उसने जवाब में लिखा कि करनाल नगर निगम ने इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया है कि शहर में कितने घरेलू और व्यावसायिक भवन बन रहे हैं।

नगर निगम ने उनसे कहा कि आपने यह तो लिखा ही नहीं कि आपको यह जानकारी कब तक की चाहिए। हालांकि नगर निगम चाहता तो वह एक साल या दो साल की जानकारी दे सकता था। लेकिन उसने दूसरा बेवकूफी वाला जवाब साइट प्लान की मंजूरी को लेकर दिया। उसने लिखा है कि पिछले दो साल में 252 साइट प्लान पर प्रक्रिया की गई। लेकिन यह पता नहीं है कि इनमें से कितने मंजूर किए गए और कितने नामंजूर किए गए।

नगर निगम करनाल के दोनों जवाबों से साफ है कि वह अवैध निर्माणों के बारे में जानकारी या तो छिपाना चाहता है या फिर देना नहीं चाहता है। जिस नगर निगम को यह न मालूम हो कि कितने साइट प्लान नामंजूर किए गए या कितने मंजूर किए गए, वह शहर को किस प्रकार चला रहा होगा, उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

स्मार्ट शिक्षा परियोजना की शुरुआत, 53 क्लासेज हुई लाइव

करनाल, (म.मो.): हरियाणा में प्ले स्कूल खोलने के साथ-साथ मॉडल संस्कृति स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इन उपायों से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, शिक्षा अच्छी होगी तो प्रदेश का भविष्य भी उज्वल होगा। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को शहर के रेलवे रोड स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहे।

मुख्यमंत्री ने विद्यालय में स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन करने के बाद इसके परिसर में ही मैथेमेटिकल पार्क को घूमकर देखा।



किसानों के समर्थन में बिना झंडे के उतरे कांग्रेसी

करनाल, (म.मो.) किसानों के समर्थन में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि करनाल के सभी बाजारों में कांग्रेस नेता दुकानदारों से हाथ जोड़कर समर्थन मांगते दिखाई दिए। इस का संयोजन कांग्रेस के जिला संयोजक तरलोचन सिंह ने किया। मुहिम की अगुआई पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बिरेंद्र राठौर, एआईसीसी के सदस्य पंकज पुनिया, पूर्व मंत्री भीम सेन मेहता, पूर्व विधायक वताराम वाल्मीकि ने की।

इस मुहिम में कृष्ण बसताड़ा, ललित बुटाना, राजेंद्र बल्ल, जोगिंदर चौहान चांदराम चौहान, राजवीर चौहान, सुरेश भारद्वाज, रणपाल संधु, डा. गीता रानी, ऊषा तुली, संतोष तेजान, सुषमा नागपाल, जोड़क्षर वाल्मीकि, प्रवीण शर्मा, इंद्रपाल आदि शामिल हुए।



सोनिया-राहुल के निर्देश पर...

कांग्रेस के जिला संयोजक तरलोचन सिंह ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पर यह प्रदर्शन अपने आप में अनूठा था। इसमें कांग्रेस के समर्थन में कोई नारेबाजी नहीं थी। केवल किसान एकता को लेकर अपील थी। प्रदर्शन में कांग्रेस ने फोकस सर्राफा बाजार पर किया। यह प्रदर्शन पूरी तरह से किसानों को समर्पित था।